[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

मिल रही है, इसीलिए वह सदन के काम में भाग नहीं लेंगे । तो जब एक मेम्बर को अधिकार है कि ज्यूंही वह मेम्बर बने, उसको मकान की सुविधा मिले, मुझे जानकारी है कि जो गैर-मेम्बर लोग हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, वह संसद् सदस्यों के आवास में अनधिकृत रूप से, जबरदस्ती रह रहे हैं, या रखवाए गये हों, या किसी पैरवी से रह रहे हैं, किसी के कहने से रह रहे हैं ।

तो एक तरफ गैर-सदस्य अनधिकृत रूप से संसद् सदस्यों के आवास में रह रहे हैं और दूसरी तरफ संसद् सदस्य जिनको अधिकार है कि उनको आवास मिले, उनको आवास नही मिल रहा है । इसी कारण से वह सदन की कार्यवाही से बाहर रहे हैं और उन्होंने पत्र लिख करके चेयरमैन साहब को दे दिया है ।

तो कितने बड़े अधिकार का हनन हो रहा है । ऐसी हिदायत दी जाए कि इस तरह से न हो... (**व्यवधान**)

श्री उपसभापति : अब इसके लिए तो चेयरमैन, हाउसिंग कमेटी को मिल कर के तय कर सकते हैं । इसमें सदन क्या कर सकता है ।

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कल पाकिस्तान से जो दस आदमी आए हैं, उनका फोटो छपा है ।

श्री उपसभापति : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री रामेश्वर सिंह : आप एक मिनट तो सुनिये ।

श्री उपसभापति : एक सेकण्ड भी नही मिल सकता है । इसकी परमिशन नहीं दी है । कोई व्यवस्था का प्रश्न नही है ।

श्री रामेश्वर सिंह : आप सुन लीजिए ।

श्री उपसभापति : जी नहीं, मैं नही सुनता ।... (**व्यवधान**) इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है । आपका तो अव्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रामकृष्ण हेगड़े : (कर्णाटक) : आप चुप रहें, तो हो जाता है ।

श्री उपसभापति : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । जबरदस्ती आप कुछ बातों को सदन में कहना चाहते हैं, जिसके लिए आपने इजाजत नही ली है और जब मैं आपको इजाजत नहीं देता, तो आपकी बात नहीं लिखी जाएगी ।

श्री रामेश्वर सिंह: मेरी बात एक मिनट सुनिये ।

श्री उपसभापति : मैंने आपकी बात सुन ली है । आपकी बात नहीं लिखी जाएगी ।

श्री रामेश्वर सिंह : *

श्री उपसभापति : देखिये, प्वाइंट आफ आर्डर मैं रूल आऊट करता हूं । लेकिन कुछ सदस्य हैं जो मेरी व्यवस्था को किसी भी समय मानने के लिए तयार नहीं हैं । उनके ऊपर उनकी पार्टी का या दल के नेता का भी नियंत्रण नहीं है ।

मैं यह बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आप बैठ जाइये । सारा सदन देख रहा है । मैं आपसे सहयोग चाहूंगा । आप बैठ जाइये ।

श्री रामेश्वर सिंह : *

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported spurt in smuggling activities on the West Coast of the country

श्री सदाशिव बागाईतकर (महाराष्ट्र) : मैं आपकी अनुमति से देश के पश्चिमी तट पर तस्करी की गतिविधियों में तेजी से वृद्धि होने के समाचार और इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

---

*Not recorded.

Sir, before the hon. Minister makes the statement, I would like to make a submission. The notice which I had given was something different from what has been printed in the List of Business. This is what I would like to bring to your notice. In the notice which I had given...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have given so many subjects.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: It is all related. I had also mentioned collusion between the administration and the smugglers.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All these things are covered in this.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: What I would like to say is, the original notice has been changed. This is what I would like to bring to your notice.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is always done. You have mentioned so many things. They have framed it in this way so that everything is covered. Whatever you have said has been covered here.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): Mr. Deputy Chairman, Sir, according to reports received by Government, the West Coast of India continues to be vulnerable to smuggling during 1981, out of the total value of smuggled goods seized all over the countr which amounted to about Rs. 40 crores the Customs Collectorates having jurisdiction along the West Coast accounted for about Rs. 19 crores *i.e.* about 47 per cent. During the first five months of 1982, out of the all India seizure figure of about Rs. 31 crores the West Coast region accounted for about Rs. 19 crores which works out to about 63 per cent. The principal items seized in the region were: gold, wrist watches, diamonds, synthetic fabrics, electronic goods and silver.

The problem posed by smuggling to the economy has constantly engaged Government's attention. Towards implementing Point No. 19 of the New 20-Point Programme which calls for continued strict action against smugglers, hoarders and tax evaders, Government have formulated a Plan for Action to intensify the anti-smuggling drive during 1982.

The West Coast of India has been identified as one of the areas vulnerable to smuggling and under the Action Plan the preventive and intelligence machinery of the Customs Department in the region is being strengthened.

A three-tier system of preventive control is exercised along the entire West Coast. Apart from intensive sea patrolling with sophisticated speed boats conducted by the Customs staff in conjunction with the Coast Guard, the three-tier system comprises Shore Guard parties which regularly patrol the coastal areas, road checking parties which guard the feeder roads to the coastline to check vehicular traffic and town preventive units which conduct regular raids and searches on the basis of information and intelligence to unearth smuggled goods in towns and cities. The entire West Coast is also covered under the Customs tele-communication network for the speedy and secret transmission of information relating to smuggling activities. The assistance of State Governments in the region and other sister enforcement agencies like Coast Guard and State Police authorities is also enlisted to take co-ordinated action against smuggling.

The pattern of smuggling along the West Coast is being kept under close and constant watch and remedial action by way of re-deployment of the preventive force and anti-smuggling equipment wherever called for is being undertaken to meet the situation.

श्री सदाशिव बागाईतकर : श्रीमन्, यह तस्करी की जो समस्या है वह कितनी भयंकर है इस के बारे में मन्त्री जी का यह निवेदन पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि उसका सही मूल्यांकन उन्होंने किया ही नहीं है। अभी-अभी 26 जून को बम्बई में देश भर

[श्री सदाशिव बागाईतकर]

के कस्टम कलेक्टर्स की जो मीटिंग हुई, जिस में आप भी उपस्थित थे और वित्त मन्त्री भी उपस्थित थे, तो उस में स्वयं मन्त्री जी ने इस को स्वीकारा है कि तस्करी को जो बढ़ावा मिला है वह बड़े पैमाने पर है और स्थिति इतनी भयंकर है कि तस्करी में 1977-78. . . .

संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : जनता पार्टी के राज में.

श्री सदाशिव बागाईतकर . . . के साल में जिस पैमाने पर वह आता था उस से चौगुना आज बढ़ोत्तरी हुई है। पार्लियामेंटरी डिपुटी मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जनता पार्टी के समय बढ़ा। जो उन्हें कहना है वह कहें, लेकिन ढाई साल से आप राज कर रहे हैं और इस का कोई सबूत नहीं है कि तस्करी कम हुई है।

श्री कल्पनाथराय : सभी तस्करों को छोड़ दिया था जनता पार्टी ने।

श्री सदाशिव बागाईतकर : बखिया का आप ने क्या किया? बखिया को किस ने छोड़ा? सब सामने आ गया है। इस लिए मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्री ने बम्बई की मीटिंग में जो बयान दिया उस के बारे में टीका-टिप्पणी सभी अखबारों ने की है जहां एक तरफ वित्त मंत्री ने कहा कि सख्ती से सरकार निपटेगी. . .तस्करी से, वहां स्वयं मन्त्री जी ने कबूल किया है कि तस्करी में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है।

दूसरी बात मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि सिर्फ सोने और दूसरी चीजों की तस्करी में ही बढ़ोतरी नहीं हुई है, दो-ढाई साल में जो रिस्ट वाचेज है उनकी तस्करी भी बड़े पैमाने पर बढ़ी है? साथ साथ तस्करी की भयानक स्थिति निबटने के लिए जो आप वेस्ट-कोस्ट पर उपाय करने जा रहे हैं, जिन का आप ने उल्लेख किया है, उस सम्बन्ध में मैं एक बात आप के सामने रखना चाहूंगा कि क्या यह सही नहीं है कि कच्छ का पूरा 200-250 मील का क्रीक का इलाका है, वहां कोई उपाय आप की तरफ से नहीं हो रहा है और दिन-दिहाड़े तस्करी के सामान का लाना-ले जाना बड़ी आसानी से वहां पर हो रहा है। वहां पर जो आप के कस्टम आफीसर्स हैं वह इतनी थोड़ी संख्या में हैं कि वह कोई कारगर उपाय कर नहीं सकते। यह भी आप के सामने आ गया है। आपने कस्टम आफीसर्स को जो साधन दिए हैं वह बहुत निकम्मे हैं और उन से कई गुना ज्यादा अच्छे साधन, स्पीडबोट वाकी-टाकी हथियार, दीव-दमन के स्मगलर्स के पास हैं। इन कस्टम आफीसर्स से आप इसका कण्ट्रोल करना चाहते हैं। स्मगलर्स के पास अच्छे किस्म का सामान है और उन का मुकाबला करना आप के अधिकारियों के लिए मुश्किल हो गया है। यह स्थिति है। जिस पैमाने पर तस्करी बढ़ रही है उस का अगर आप को सही अन्दाजा नहीं है तो उसका मुकाबला करने के लिए आप कारगर उपाय नहीं कर पायेंगे। अकेले सोने की बात करें तो यह हिसाब लगाया गया है कि बम्बई में 25 हजार तोला सोना बेचा जाता है। उसमें से 10 हजार तोला स्मगलिंग का रहता है। इतने बड़े पैमाने पर बम्बई जैसे शहर में तस्करी चलती रहती है। आंकड़ा यह है कि इस साल के अन्दर-अन्दर अकेले सोने को लेकर 2550 करोड़ तक की तस्करी होने जा रही है क्योंकि अकेले बम्बई शहर में 500-700 करोड़ रुपए का सोना आ रहा है। यह स्थिति थी एक जमाने में कि महीने में दो-चार मर्तबा जिस को उन की भाषा में उन की जार्गन में लैण्डिग कहते हैं वह होती थी। अब यह स्थिति है कि पूरे वेस्टकोस्ट में तीन-बार लैण्डिग एक दिन में हो रही है। उस में सोना आ रहा है। उन में बड़े पैमाने पर घड़ियां आ रही हैं, बड़े पैमाने पर वीडियो या दूसरी तरह के इलेक्ट्रोनिक्स आ रहे हैं। साथ साथ जो आर्टीफिशियल फाइबर है, कपड़ है, वह भी ट्रक के ट्रक भरकर इधर-उधर किया जाता है बड़े पैमाने पर। उस

का भी तस्करी में समावेश हो गया है। जो आप लोग माल डिटेक्ट करते हैं, आप के कस्टम अधिकारियों का जो स्टैण्डर्ड है उस के मुताबिक कहा जाता है कि वह स्मगलिंग का मुश्किल से 10 परसेंट होता है। अखबार में जो हम पढ़ते है कि इतना माल अधिकारियों ने पकड़ा तो वह कुल मिला कर मुल्क भर में---वेस्ट कोस्ट में जो भी रहा होगा---मुश्किल से 10 परसेंट होता है। श्रीमान, कितना बड़ा खतरा देश के आर्थिक ढांचे को उत्पन्न हो रहा है जब यह स्वीकार किया जा रहा हैं कि साल भर के अन्दर स्मगलिंग की इकोनोमी में 10 हजार करोड़ के आसपास पैसा उपलब्ध होने जा रहा है। यह आंकड़े हैं। तो मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आप ने जो बयान दिया है उस में पश्चिमी तट की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है लेकिन वहां की इन हकीकतों को आप ने नजर अंदाज कर दिया है। और यह मामला सिर्फ पुलिस और कस्टम का ही नहीं है। मेरा तो सरकार पर आरोप है कि सरकार के पास तस्करी को रोकने के लिये जो पोलिटिकल विल होनी चाहिए, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो संकल्प होना चाहिए उस का ही अभाव है और इसी लिये तस्करी को रोकना तो दूर रहा तस्करी दिन ब दिन बड़े पैमाने पर पूरे देश में बढ़ रही है और उसे ग्रस्त कर रही है। और यह खाली पश्चिमी तट का ही सवाल नहीं है आप जानते हैं कि गोरखपुर, बस्ती और नैपाल के बार्डर के इलाके में कितने भयंकर पैमाने पर यह तस्करी जारी है और सरकार के पास कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति उस को रोकने की नहीं है। सरकार की ओर से ऐसा भी कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है कि तस्करी करने वालों के मन में किसी प्रकार का डर पैदा हो। अभी अभी जो गोआ में बखिया का काण्ड हुआ उस से एक बात साफ हो गयी कि सरकार के अलग अलग जो अंग हैं उन में आपस में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। आप के एक दफ्तर के लोग वारण्ट लेकर जाते हैं और दूसरे विभाग के लोग उस को छोड़ देते हैं। इस तरह की जो घटना हुई उस के बाद जो वहा का चीफ जेलर था वह भी पकड़ा गया है और उसके घर में सोना पकड़ा गया है। जो कुछ मैं कह रहा हूं उस से एक बात यह साफ हो जाती है कि तस्करी की बढ़ोतरी हो रही है और एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा हिस्सा उस के साथ है। आप की कस्टम और पुलिस उसके साथ है और मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि राजनीतिक प्रश्रय भी उन को बड़े पैमाने पर मिल रहा है और इस कारण से तस्करी करने वाले लोग इतने निर्भीक हो गये हैं कि वे दिन में खुले आम कच्छ के सारे इलाके में दिनदहाड़े अपना सारा काम कर रहे हैं और उन की रोकथाम का कोई उपाय सरकार के पास नहीं है। सरकार सिर्फ देखती रहती है। तो इसलिये मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आप बाकी सारे उपायों की चर्चा कर सकते हैं कि आप उनको स्पीड बोट देंगे बाकी टाकी का सामान देंगे, और दूसरी चीजें देंगे लेकिन जो इच्छा शक्ति का अभाव राजनीतिक क्षेत्र में आया है उस का बंदोबस्त आप कैसे करेंगे ? और इस के संबंध में एक उदाहरण मैं जरूर देना चाहूंगा। उस का उदाहरण यह है कि अभी-अभी कुछ दिन पहले गुजरात सरकार के राज्य मंत्री श्री खंबोजा जी ने एक स्टेटमेंन्ट में कहा है--और वह अखबारों में आया है, गुजराती और मराठी अखबारों में आया है जिस में उन्होने कहा है कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो एक्टिंग प्रेसीडेन्ट हैं डा० महीपत मिश्र, जो दूसरे सदन के सदस्य भी हैं, उन्होंने गवर्नर को खुली चिट्ठी लिख कर दो स्मगलर्स की रिहाई की मांग की है। यह स्टेट मिनिस्टर का बयान है। दो हफ्ते पहले दो स्मगलर्स जो पकड़े गये थे उन्होने जो बयान दिया है उसमें उन्होने फिर उन का नाम दे दिया है कि उन की तरफ से

[श्री सदाशिव बागाईतकर]

हम को मदद मिलती है। तो ऐसे कितने ही उदाहरण हैं और इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिमी तट पर क्या और नेपाल बार्डर पर क्या और पंजाब की सरहद पर क्या इस तस्करी को रोकने के लिये राजनीतिक इच्छा आप कहां से लायेंगे और रूलिंग पार्टी के लोग भी अगर उस में हिस्सेदार हो जायेंगे तो तस्करों का बंदोबस्त कैसे होगा। कलाधरी ब्रदर्स का क्या हुआ? बखिया का क्या हुआ? यह सब आप के सामने है। इस लिये अगर सरकार की सारी राजनीतिक और शासक दल कटबैंक को हासिल करने की कोशिश में तस्करों के साथ सांठगांठ बना कर चलता रहेगा तो मै नहीं समझता कि तस्करों के लिये कोई उपाय हो सकता है। तस्कर सिर्फ किनारों पर घूमते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ हफ्ते पहले बखिया के ब्रदर इन ला दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में पकड़े गये। उसके पास जो ट्रांजेक्शन उसने दो महीने में किये थे उसका पूरा हिसाब मिल गया और इस दो महीने के अन्दर उसने 45 करोड़ रूपये का सोना इधर से उधर करने का काम किया। इसका पूरा नोटिंग उसके साथ पकड़ा गया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आपने इस पर कोई उल्लेख नहीं किया सरकार अगर कड़ाई से इसको रोकना चाहती है तो सरकार ने जो कानून बना रखा है कंफिस्केशन का कानून, क्या सरकार इसके लिए तैयार है कि किसी भी स्मगलर को जब स्मलिंग में पकड़ा जाएगा तो सरकार उसकी सारी सम्पत्ति को अपने कबजे में ले लेगी उसको कंफिस्केट करेगी और आज जो कानून है उसकी धाराओं में जो एंटिसिपेटरी बेल उनको मिल जाती है या उनको जेल में आप रखते हैं उससे कोई लाभ नहीं है क्योंकि जेल के अन्दर वह जैसा व्यवहार करते है उससे उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। मेरा सवाल यह है कि जो स्मलिंग करने वाले लोग हैं उनकी प्रापर्टी कंफिस्केट सरकार करेगी और जो बाकी लोग उनके साथ मिले हुए हैं उन पर आप कड़ी कार्यवाही करने के लिए तैयार है? इसके साथ ही राजनीतिक संकल्प शक्ति बनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे क्योंकि इसका कोई उल्लेख आपके बयान में नहीं है। आप अपने वक्तव्य में उसका भी उल्लेख करें।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : श्रीमन् माननीय सदस्य ने जो कालिंग अटेंशन नोटिस दिया है उसमें खास तौर पर शासन का ध्यान वेस्ट कोस्ट में स्मलिंग ऐक्टिविटीज और उसके लिए सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों की ओर दिलाया है। लेकिन उन्होने जो प्रश्न उठाये है उसमें वेस्ट कोस्ट को छोड़कर, अन्य ..... **(व्यवधान)**

श्री सदाशिव बागाईतकर : श्रीमन् मैने गुजरात के लोगों की चर्चा की। वह वेस्ट कोस्ट का हिस्सा है।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : पहले पूरी बात सुन लीजिए। अगर कोई बात रह जाए तो फिर बोलिए। वेस्ट कोस्ट को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों का भी उन्होंने जिक्र किया है। मैं अपने उत्तर को विशेष तौर पर वेस्ट कोस्ट के बारे में जो जानकारी चाही है उस तक ही सीमित रखूंगा।

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने अनेक प्रश्न उठाये है। जिन महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है उसमें सबसे पहला प्रश्न यह है कि तस्करी बड़े व्यापक पैमाने पर फैल रही है। गोल्ड और वाचेज की स्मलिंग का उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने यह बताया है कि शासन के जो संबंधित महकमे हैं उनके पास साधन अच्छे नहीं है और राज-

नीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। बखिया को भी उन्होंने याद किया अपने प्रश्न में और गुजरात के किसी राज्य मंत्री के वक्तव्य का भी उल्लेख किया है। आखिर में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो स्मगलर हैं उनकी प्रापर्टी को कंफिस्केट करना चाहिए।

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) : गवर्नमेन्ट ही स्मगलर हो तो क्या होगा?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : श्रीमन् मैं सबसे पहले इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि शासन इस बात के लिए सजग और सतर्क है कि तस्करी का फैलाव हो रहा है। हम इससे इंकार नहीं करते। उन्होंने बम्बई की एक कांफ्रेन्स का भी हवाला दिया। मैं भी उस कांफ्रेन्स में मौजूद था जो कस्टम कलक्टर्स की कांफ्रेन्स थी और यह कांफ्रेन्स भी इसलिए की गई थी कि कस्टम्स और दूसरे अधिकारी से विशेष तौर पर ताकीद की जाए कि इस दिशा में वह ऐडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव के साथ-साथ दूसरे जो भी कदम उठाये जा सकते हैं वह उठायें। एक पांच-सूत्री कार्यक्रम इसके लिए बनाया है। उस कार्यक्रम की पूर्ति के लिए, उनको अलर्ट करने के लिये, उनको जागृत करने के लिए, उनको सावधान करने के लिए, उनको दिशा निर्देश देने के लिए, इस प्रकार की कांफ्रेन्स की गई। और उसके परिणाम पहले भी अच्छे हुए और हम को उम्मीद है कि जो तस्करी का फैलाव हो रहा है उसको रोकने में शासन सक्षम है और उसमें सफल होगा।

जहां तक इनके प्रश्न है गोल्ड और वाचेज के बारे में वह मैं जानकारी सदन के सामने रखना चाहता हूं। 1979 से 1982 तक के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं उनको माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1979 में स्मगलर्स से जो गोल्ड जब्त किया गया है वह 112 लाख की कीमत का था। 1980 में 85 लाख का, 1981 में 190 लाख का और 1982 मई तक 568 लाख का गोल्ड उनसे जब्त किया गया। इसी तरह से वाचेज के बारे में जो आंकड़े मेरे पास हैं वे मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1979 में 221 लाख की कीमत की घड़ियां जब्त की गई। 1980 में 217 लाख की, 1981 में 259 लाख की और 1982 मई तक 193 लाख की वाचेज जब्त की गई। सिंथेटिक फाइबर, सिल्वर, डाइमंड और अदर आइटम्स है उनके बारे में भी माननीय सदस्य को जानकारी प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1979 में 24 करोड 83 लाख का कुल माल जब्त हुआ। 1980 में 33 करोड़ 50 लाख का, 1981 में 18 करोड़ 79 लाख और मई, 1982 तक 19 करोड़ 83 लाख के सिंथेटिक फाइबर्स, सिल्वर, डाइमंड आदि पकड़े गये। इन आंकड़ों से पता चलेगा कि जहां तक शासन के संबंधित विभाग, अधिकारी और कर्मचारियों का सवाल है उनको पूरे साधन और सुविधाएं दी जा रही है और निश्चित एक तैयार किये हुए कार्यक्रम के मुताबिक उन स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। माननीय सदस्य ने राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात कही है। मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम का जो 19 वां कार्यक्रम है वह इसी बात के लिये खासतौर से रखा गया है। जो स्मगलर्स हैं जो टैक्स इवेडर्स हैं जो इससे संबंधित का कानून का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, ऐसा इस कार्यक्रम में है।

श्री सदाशिव बागाईतकर : आपके दल में भी है।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : पूरी बात तो सुन लीजिए। आप बोलते ही जा रहे

[श्री सवाई सिंह सिसोदिया]
हैं। इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए निश्चित कार्यक्रम बनाया गया है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो जो हमारा चार सूत्री कार्यक्रम है वह देख लें :

1. Strengthening of preventive and intelligence machinery.

2. Intensification of application of the provisions of the COFEPOSA Act.

4. Economic and legislature measures.

4. Bilateral arrangements and co-operation with neighbouring countries.

हर प्रकार से जो एक्शन इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए लिया जा सकता है वह शासन की ओर से लिया जा रहा है और उसके परिणाम भी अच्छे निकले हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति के बारे में जैसा मैंने निवेदन किया है यह हमारी पार्टी का कार्यक्रम है। केन्द्रीय शासन का जो संकल्प है उसमें यह एक महत्वपूर्ण अंग है। उस कार्यक्रम के मुताबिक इस महकमे द्वारा एक्शन लिया जा रहा है।

बखिया के बारे में माननीय सदस्य ने बहुत कुछ कहा है। यह कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। राजनीतिक कोई संकल्प नहीं था। उसको पकड़ने की कार्रवाई नहीं की गई। माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि 1962 से यानी पिछले 20 साल से यह व्यक्ति इस प्रकार के काम में लगा हुआ है। 1974 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिटेंशन आर्डर इशू किया। 1975 में इसको पकड़ा गया।

श्री सदाशिव बागाईतकर : यह एक दिन भी जेल में नहीं रहा। हास्पीटल में ही रहा।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : इमरजेंसी जब समाप्त हुई उसके बाद यह छूटा है...

श्री सदाशिव बागाईतकर : मंत्री जी, आपको पता नहीं होगा कि आर्डर आपने निकाले लेकिन वह एक दिन भी जेल में नहीं रहा। वह होस्पीटल में ही रहा।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : 1975 में यह पकड़ा गया और 1977 में यह छूटा है, consequent to revocation of Emergency.

श्री सदाशिव बागाईतकर : आप रिकार्ड उठा कर देख लें वह हास्पीटल में ही रहा।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : इसके खिलाफ 1980 में 'काफीपोसा' के अंडर वारण्ट जारी किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट में रिट पेटीशन दायर करके इंजेक्शन आर्डर लिए गए। इस पर गुजरात गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ काफीपोसा के अंडर डिटेंशन आर्डर इशू किया। जुडिशियल कमिशनर के सामने लाया गया। गोवा जेल में बन्द रहा लेकिन वहां से वह भाग गया। इसमें जेल के अधिकारियों की गलती है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद पूरे कस्टम डिपार्टमेंट के संबंधित महकमों की सतत कार्रवाई के परिणामस्वरूप उसने सरन्डर किया और उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन जुडिशियल कमिशनर के कोर्ट में काफीपोसा के अंडर गुजरात गवर्नमेंट ने स्टे आर्डर जारी किया जिसमें यह कहा गया कि जब तक रिट पेटीशन का फैसला नहीं होता तब तक गिरफ्तार न किया जाए। लेकिन कस्टम डिपार्टमेंट ने कस्टम्स् एक्ट के अन्तर्गत जो अपराध उसने किए थे उसके संबंध में केस दायर हुए, वारन्ट इशू हुए और गिरफ्तार किया गया। अब फिर

अदालत के आर्डर से अभी दो चार दिन पहले जमानत पर छूटा है। इसमें शासन की ओर से जहां-जहां पर जिन हाई कोर्ट्स में रिट पेटिशन हुए हैं और इन्टैरिम आर्डर हुए हैं उनको एक्जामिन किया गया है और उनको वैकेट करने की कोशिश की जा रही है। शासन की ओर से कोई ढिलाई किसी किस्म की नहीं की गई है। इन्टैरिम आर्डर वेकेट भी किया गया है। जुडिशियल फंक्शनिंग के बारे में इस समय मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं। जब जुडिशियल अथोरिटीज की ओर से इन्टैरिम आर्डर इशू हो जाता है तो महकमे की ओर से, शासन की ओर से, कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है जब तक कि उसका निर्णय नहीं हो जाता है। इसलिए बखिया को कोई मदद करने की बात किसी को कल्पना में भी नहीं करनी चाहिए। उसको किसी प्रकार की सहायता देने की बात या ढिलाई की गई हो या कोई एक्शन जो समय पर लेना चाहिए वह नहीं लिया गया हो, इसमें कोई सत्य नहीं है। इसलिए मैं उनके भ्रम को दूर करना चाहता हूं। इसमें जितनी भी रोक की कार्यवाही या गिरफ्तारी रोकी गई है वह हाई कोर्ट के आदेश से हुआ है। उसके अनुसार रोक हुई है। शासन की ओर से कोई ढिलाई का काम नहीं हुआ है।

दूसरी बात उन्होंने गुजरात के किसी माननीय उपमंत्री जी या राज्य मंत्री जी का हवाला देकर कही है, उसके बारे में इस समय मेरे सामने कोई स्टेटमेंट नहीं है। जहां तक हमारी जानकारी है, किसी राज्य मंत्री के स्टेटमेंट से संबंधित या वहां के जो कांग्रेस के प्रैजीडेंट हैं उनके संबंध में कोई बात का ताल्लुक है, यह बात अखबारों में छपी होगी। इस समय यह मेरे सामने नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि गुजरात के क्षेत्र में या कच्छ के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जो स्मगलिंग से संबंधित है उसको स्पेयर नहीं किया गया है। उसके खिलाफ जो कार्यवाही हो सकती है वह की गई है।

कॉन्फिसकेशन के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि —

Forfeiture of properties under the SAFEMFOPA: Appropriate action was also taken to forfeit the properties of smugglers and foreign exchange racketeers under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act, 1976 up to April, 1982. Forefeiture action has been initiated in 2,285 cases, covering properties valued at Rs. 36.91 crores. Orders of forfeiture have already been issued by the competent authorities in 1,322 cases involving properties valued at Rs. 11.28 crores. And here also some of the parties have gone to the Supreme Court, and they have obtained injunction orders Therefore, whatever action Government should have taken, it has taken.

श्री सदाशिव बागाईतकर : वह कोर्ट में गया है।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : सुप्रीम कोर्ट में रिट पैंडिंग है और जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता, शासन की ओर से जो एक्शन लेना चाहिये वह लिया जा रहा है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मेरे सहयोगियों ने बहुत सारी बातें कह दी हैं। उन सब को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह तस्करी का रोग हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। अगर मैं यह कहूं कि भारत में यह तीसरी अर्थ व्यवस्था है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार की गलत नीतियों के कारण करोड़ों रुपया रोज आता है और तस्करी करने वाले करोड़ों रुपयों का

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

माल देश के अन्दर लाते है। इन दोनों विषयों पर आपने प्रकाश नहीं डाला है। जहां तक वेस्ट कोस्ट का सवाल है, मैं इस बारे में दो-तीन बातें पूछना चाहता हूं।

श्री उपसभापति : कालिंग एटेंशन भी वेस्ट कोस्ट के बारे में ही हैं। दुनिया भर की बातें इसमें नहीं हो पाएंगी।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : दूसरे देशों से भी इस मामले का संबंध है। मैं यह जानना चाहता हूं कि किन-किन देशों से और खास करके किन-किन देशों से सोना और डायमन्ड आ रहा है? सोना और डायमन्ड विशेषत: ऐसी मंहगी चीजें है जिनकी तस्करी खास करके वेस्ट कोस्ट से होती है और यह चीजें दुबाई से आती हैं। आज से नहीं, पिछले 20-25 नहीं 50 सालों से दुबाई इनका सेंटर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसको रोकने के लिये आपने क्या किया है? दूसरा, यह भी आपको मालूम है कि पिछले दिनों सोने की तस्करी और बढ़ी है। इसका कारण क्या है? अन्तरराष्ट्रीय बाजार के अन्दर सोने के भाव गिरे क्योंकि रूस को अपने कर्जों को अदा करने के लिये पैसा देना पड़ा, ईरान को देना पड़ा, साउथ अफ्रीका को पैसा देना पड़ा। इसलिए सोने के भाव अन्तरराष्ट्रीय बाजार में पिछले डेढ़, दो सालों में घटे। इस कारण से तस्करी सोना लाने की हुई है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब आपको यह मालूम हुआ कि पिछले दिनों अन्तरराष्ट्रीय बाजार के अन्दर सोने के भाव में गिरावट आई है तो उस समय आपने तुरन्त क्या किया, किन-किन देशों से संबंध स्थापित किया और खासकर इंटरपोल जो है, जो इसका विभाग है उसके साथ क्या क्या संबंध स्थापित किये और क्यों कार्यवाही की?

आप केवल सीमा पर बम्बई का जिक्र कर रहे है। आपको मालूम है कि कोलाबा के अन्दर में जो बस स्टेशन है वहां पर दिन दहाड़े यह होता है। मैं नाम इसलिये ले रहा हूं जिससे आप उस अड्डे को पकड़ लें। हफ्ते में कम से कम तीन बार यह घटना होती है। पुलिस वालों को पड़ोसी फोन करते है और पुलिस वाले पहुंचते ही नहीं। जब सारा माल चला जाता है तब चार-छ: घंटे के बाद पुलिस आपकी पहुंचती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बड़ा पक्का इतजाम किया है लेकिन आप बम्बई के बाजार में जाइये, फोर्ट एरिया में खुले बाजार में मिले ना तस्करी का सामान बिकता हुआ। इसका आपने क्या किया? कौन लोग आपने पकड़े हैं? किन लोगों को पकड़ा है? तमाम सामान जो बिकता है उसको आप पकड़ते नहीं और आपके आफिसर मिले हुए हैं। मैंने यह नहीं कहा कि आप की इच्छा शक्ति नहीं होगी, लगता है, है। लेकिन कहना चाहता हूं कि नहीं हैं। आपके 20-सूत्री प्रोग्राम के अन्दर यह है। लेकिन कारण क्या है? आपके आर्गनाइजेशन का ढांचा इतना भ्रष्ट है आपके ऊपर के श्री प्रणब बाबू और आपकी इच्छा शक्ति होते हुए भी नीचे के जो आपके कार्यकर्ता और नेता है वह तस्करों का साथ देते हैं, तस्करी से खाते हैं और तस्करी से कमाते हैं। इसको रोकने के लिये आप क्या करेंगे यह आप बता दीजिये कि किन राजनैतिक कार्यकर्ताओं, चाहे वह किसी भी दल के हों, जो तस्करी से संबंधित है, आपने ऐसे कितने लोगों को पकड़ा है। नेपाल बार्डर... (व्यवधान) ...यहां मैं पूछ रहा हूं कि अगर कांग्रेस (आई) को न पकड़ो तो दूसरों को पकड़ो।

Not even one political worker has been arrested. They are all there.

मैं उदाहरण देता हूं । अभी जैसलमेर...

श्री उपसभापति : उनको पकड़ेंगे तो कहेंगे कि पोलिटिकली किया है... (व्यवधान) ...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : कांग्रेस (आई) की बात कर रहा हूं। अभी आपके मंत्री हैं, हैल्थ मिनिस्टर है राजस्थान में.... (व्यवधान)... हैल्थ मिनिस्टर हैं। 9 जुलाई को जैसलमेर गये । वहां पर तस्करों ने उनका स्वागत किया, दावत उड़ाई, ये कौन हैं। ये ऐसे पोलिटिकल नेता नहीं जैसे आप और हम हैं। ये पुराने आई० पी० एस० आफिसर हैं जो पहले प्रोविंसियल सर्विस के आदमी थे। वह आज आपके मंत्री है। वह तस्करों के साथ खाना खाते हैं । 9 जुलाई की बात कर रहा हूं । आप कहते हैं कि इच्छा शक्ति है । कहां इच्छा शक्ति है ? आपको मालूम था कि बखिया के श्वसुर साहब जो हैं उनको बोट है, लौंच है । चन्द्रसागर नाम की वोट कब से चल रही है लेकिन बोट अब पकड़ी गई । लेकिन चन्द्रसागर जो है वह उसके श्वसुर के नाम से रजिस्टर्ड है जो कि वर्षों से चल रही थी। क्यों नहीं पकड़ा आपने ? कारण क्या है ? आफिसर मिले हुए हैं, नेता मिले हुए हैं ।

अब मैं दूसरी तरफ आता हूं । आप कहेंगे संबंधित नहीं है, जवाब न दीजिये । लेकिन मत दीजिये जवाब । पंजाब से तस्करी हो रही गेहूं तथा शूगर वहां से जाता है । चीनी कहां से जाती है, वह जाती है मुजफ्फरनगर से । अगर आप कहेंगे तो मैं आपको नेताओं के नाम बता दूंगा कि फलां फलां है और फलां फलां दिन शूगर गई। ऐसे ही वहां से माल आता है। बंगाल के बार्डर पर और पाकिस्तान के बार्डर पर यह खेल है जो ये खेलते हैं। इसमें आपके आफिसर भी शामिल हैं, पाकिस्तान के आफिसर भी शामिल हैं और बंगलादेश के आफिसर भी शामिल हैं। रेल के डिब्बे आते हैं। रेल के डिब्बों में जो लकड़ियां लगी हुई हैं उनको ये ढीली रखते है और उसके अन्दर सामान भरा रहता है और वह भर लाते है उसमें कपड़ा और वी० डी० ओ० और वह यहां आ जाता है। बीच में दिखाने के लिये हो जाता है कि चेकिंग हो गई। बार्डर क्रास किया और सामान चला जाता है। आपने इसमें किनको पकड़ा है। कोई नहीं पकड़ा है अभी । मेरे मित्र ने अभी एक नाम लिया। लेकिन अगर मैं नाम लूंगा तो वे भड़क जायेंगे गलाधारी ब्रादर्स का। कौन नहीं जानता गलाधारी ब्रादर्स स्मगलर्ज हैं। उनसे आपने ठेका किया है। मैं अपने जानकार सूत्रों से कह सकता हूं। आज कई करोड़ रुपया छिपा कर गलाधारी ब्रादर्स दे रहे हैं पार्टी के फन्ड में । आप का जो होटल बन रहा है, दैट इज बिइंग फाइनेंस्ड् बाई देम । (व्यवधान) आपने गलाधारी ब्रादर्स को (व्यवधान) मेरी बात आप सुनिये। और आप कहते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति है अगर होती तो आप कहते कि नहीं हम राजनीतिक आधार पर, गलत आधार पर... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : बहुत सवाल हो गये, अब उनको जवाब देने दीजिये ।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी (महाराष्ट्र) : मैं आपको खाली सबमिट करता हूं । माथुर साहब । यह क्या राम राज्य हैं। यह आदमी लोग चलाने वाले हैं इसलिये ऐसे ही चलने वाला है।

श्री उपसभापति : आप कुलकर्णी जी का जवाब मत दीजिये। आप अब समाप्त करें।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जो मेरी और इनकी बात हुई।

श्री उपसभापति : उसको छोड़िये आप।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप कहते हैं कि इच्छा शक्ति है, अगर इच्छा शक्ति होती तो यह जितने स्मगलर्ज हैं उन के खिलाफ जो मुकदमें है वे आप वापिस क्यों लेते ? आपने मुकदमें वापिस लिये हैं। तो मेरा कहना यह है कि आज अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति 19–20 नम्बर का सूत्र है वह न रख कर अपने दल के भीतर, शासन के भीतर लाइये तब कुछ होगा।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : सर्वप्रथम यह गलाधारी ब्रादर्स के बारे में जो उन्होंने गलत आक्षेप लगाये हैं उनका मैं खंडन करता हूं। गलाधारी ब्रादर्स से करोड़ों रुपया चन्दा लेने वाली बात बेबुनियाद मनघंड़त और झूठ है। इस प्रकार की बिना किसी आधार के ऐसी कोई बात कहना किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता। मेरा निवेदन यह है कि यह सब गलत है। इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है गलाधारी ब्रादर्स के बारे में सुप्रीमकोर्ट में केस पेंडिग चल रहा है। इसलिये भी उसकी कोई चर्चा यहां नहीं हो सकती और जो भ्रष्टाचार की बात उन्होंने उठाई है उसका मैं जोरदार शब्दों में खंडन करता हूं। राजस्थान के किसी मंत्री का हवाला दे कर कहा, राजस्थान के किसी मंत्री के वक्तव्य के बारे में कोई उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है और इस समय मेरे सामने नहीं है हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात इस समय नहीं है। यह बिलकुल गलत है मैं उसका भी खंडन करता हूं। दूसरा जो प्रश्न सोने के बारे में उठाया है सोने के तस्करी के बारे में सवाल उठाया है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि सोने का जो भाव हमारे यहां है और जो इंटरनेशनल प्राइस है उसमें काफी अन्तर है और इसी वजह से ही स्मगलिंग होती है और पिछले दिनों में इस विषय में काफी वारदातें सोने की स्मगलिंग की हुई हैं और शासन ने समुचित कार्यवाही उनके खिलाफ, स्मगलर्ज के खिलाफ की है और उसका परिणाम यह है कि जो आंकड़े मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये हैं सोने के संबंध में उनसे जाहिर होता है कि शासन की ओर से तुरन्त एक्शन इसमें लिया गया है और यही कारण है कि सिर्फ मई, 1982 तक पांच करोड़ 68 लाख रुपये का सोना जब्त किया है। अगर एक्शन न लिया होता और शासन सतर्क न होता तो पिछले वर्ष के आंकड़ों के मुकाबले में आप देख सकते हैं कि इसमें तुरन्त कार्यवाही की गई है और किसी को भी स्पेयर नहीं किया गया जहां तक सोने का संबंध है,... (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या करेंगे उसका (व्यवधान)

SHRI SAWAI SINGH SISODIA: From December, 1980 to today there has been an increasingly attractive margin of profit for smuggling gold into the country due to the continuous fall in international price. In December, 1980 the average margin of profit of gold being smuggled into India was Rs. 98 per ten grammes. This rose in January, 1981 and fluctuated in the region of Rs. 150 to Rs. 250 per ten grammes till December, 1981. During January, 1982 the average margin of profit for gold being smuggled into India was Rs. 320 per ten grammes and stood at about Rs. 317 per ten grammes during January, 1982.

इन्हीं हालात की वजह से स्मगलिंग का जिन ज्यादा लोगों ने इसमें सहारा लिया है, उनके खिलाफ तुरन्त एकशन लिया गया। काफेपोसा के बारे में जिक्र किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शासन की ओर से कस्टम डिपार्टमेन्ट, पुलिस डिपार्टमेन्ट के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी इसमें नहीं छोड़ा गया, उनका हाथ पाया गया तो उनके खिलाफ भी काफेपोसा के वारण्ट इश्यू किये गये हैं। यह फिगर्स की मोटे तौर पर जानकारी मैं रखना चाहता हूं। The all India figure of orders issued under COFEPOSA is 354 in 1980; the number of persons detained in that year was 298; orders issued in 1981 were 360 and the persons detained were 265: orders issued in 1982 upto 3-7-1982 were 292 and persons detained are 264. I have State-wise break up also... मैं सदन की जानकारी के लिए इसमें वह भी प्रस्तुत करना चाहता हूं...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is not necessary.

SHRI SAWAI SINGH SISODIA: As on 3-7-82, there were 240 persons in actual detention.

यह 240 है और जो कस्टम और पुलिस के अधिकारी हैं उनको भी काफेपोसा एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। आपने कहा, Then what measures have been taken against persons who are selling on foot-path? In view of this open display and sale of smuggled goods, specially in the metropolitan cities, collectors were directed to conduct concerted drive to step up the raids and search on shops and stalls known to be dealing in such goods in the principal markets of the major cities.

During 1981, such raids and searches were conducted on all India basis coordinated by the DRJ, the operations covering cities such as Bombay, Delhi, Calcutta, Madras, Bangalore, Pune etc. resulted in the search of 2289 shops and stalls leading to seizures valued at about Rs. 49.70 lakhs. During the first 5 months of 1982, 995 such raids and searches were conducted yielding goods valued at Rs. 41.37 lakhs. During the corresponding period of 1981, 1202 such raids and searches yielded goods valued at Rs. 14.26 lakhs, showing an increase by 190 per cent in the resultant seizures.

श्री पी० एन० सुकुल (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, एक क्लेरिफिकेशन इसी से संबंधित है माथुर साहब ने अभी पूछा था और मंत्री जी ने जवाब दिया था। श्रीमन्, माथुर साहब ने कहा कि गलाधारियों से लाखों रुपया चन्दा सरकार ने लिया...(व्यवधान) आपने कहा कि सरकार ने नहीं लिया। क्या आप यह कह सकते हैं कि आपके पहले जो जनता सरकार थी, उसने भी नहीं किया? अटल बिहारी बाजपेयी और मोरारजी देसाई दोनों ने मिलकर ... (व्यवधान) पिछली सरकार ने भी नहीं लिया ...(व्यवधान)

श्री उपसभापति: हो गया, आपने कह दिया, छोड़ दीजिए...आप शांत रहिए।

श्री पी० एन० सुकुल: क्योंकि माथुर साहब की अपनी पार्टी का सवाल है...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has refuted it.

SHRI P. N. SUKUL: It is very important and very relevant.

SHRI DINESH GOSWAMI (Assam): Mr. Deputy Chairman, even if one goes through the written statement of the hon. Minister, it is apparent that smuggling on the west

[Shri Dinesh Goswami]

coast is on the increase because according to his statement whereas in 1981 the seized goods from the west coast valued at about Rs. 19 crores, in the first five months of 1982 goods worth about the same value were seized. It is also a fact that black money arising out of smuggling and sale of smuggled goods is a crucial problem for the economy of our country. Further, however much one may deny, the evil effect of smuggling on the political system in our country is becoming a real threat. It cannot also be denied that what we see is only the tip of the iceberg because only a small fraction of the smuggled goods is seized. A large percentage of smuggled goods is not seized and it goes out of detection of the Government. The very last statement of the hon. Minister was that more than 2,000 shops are involved in the sale of smuggled goods. If you go to the Delhi market, you will find that smuggled goods are sold in the open. This is so in Calcutta also. I often go to Assam by rail and on the way I find lot of smuggled goods in many of the railway stations in the north eastern region. They are all smuggled from China and are sold in the open. The entire Government machinery is showing total disregard to this. It is also a fact that Bhakia has escaped from the jail. After he has surrendeed, Sir, he has been granted bail. Can you expect, in any other case even, even in a case of a petty theft, that a person who has escaped from jail and who has surrendered, would be allowed to go on bail, on a bail of ten thousand rupees? After all, the judiciary is itself a part of the administrative machinery. Therefore, if a person who escapes from the jail, about which so much has been written in the country, if he comes and surrenders and is allowed to go on a bail of ten thousand rupees, then one must also have a reasonable suspicion that the net of the smuggling or the net of the smugglers not only encompasses the political personalities, but also the judicial field, and that there is also a possibility that their net encompasses the judicial field and that makes us all greatly worried. Therefore, I would like to know one or two things. Because the time is short I would straightway come to some of the questions. Smuggling, after all, cannot be a one-way operation. It involves the other countries, two more countries or more than two countries, and many of the smugglers are big operators. Have you been able to identify the links of the top operators of our country with the top operators of the other countries and have you been able to find out as to how the transfer of money and the materials takes place? I am asking this question because, after all, it is no use just arresting the person who is coming in a car because the smaller fish are always allowed to be arrested. Therefore, I would like to know whether the linkage has been established and whether you have been able to find out how the transfer in terms of goods as well as finance is taking place.

1 P.M.

Then, Sir, my second question is this. Have you been able to make any asessment of the total amount involved in the smuggling in the country? What you have seized is only a tip of the iceberg. In other to arrest the effect of smuggling on the economy, on the total economy, of the country, have you been able to make any assessment of the total amount involved in smuggling? At least insofar as it relates to West Coast, will you give us some figures particularly with regard to this area as to what your assessment is of the total amount involved in the smuggling operations in the West Coast area? If you are not able to make any such assessment, then the Finance Ministry's calculations in many fields are likely to go awry and, therefore, I would like to know whether you have been able to make any assessment and, if so, what the asessment is in this regard.

SHRI SAWAISINGH SISODIA: Sir, so far as the question of release of Bakhia on bail is concerned, really it is a matter of concern. But this order was passed by the judicial authorities and appropriate action by the Customs Department is being taken. This order is being opposed and the other interlocutory orders which have been passed by the different judicial authorities are also being opposed by the Department.

Then, Sir, as far as the top operators in the foreign countries and in our own country are concerned, our Intelligence Department is doing the needful in this matter. But it will not be in public interest to place all that information before the House.

Regarding the total assessment of the smuggled goods, their value, etc., it is quite impossible to have any sort of assessment. But, whenever there is any news received by our Intelligence organisation that there are some gangs or some smugglers who are engaged in such operations, in smuggling, in bringing some things into our country and taking something out of the country, appropriate action is being taken. So, Sir, I think the other questions raised by my honourable friend have been fully replied to earlier

SHRI DINESH GOSWAMI: Have you not got any assessment of the total amount involved in the smuggling? Otherwise, how will you know its effect on the economy?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He says it is not possible.

SHRI SAWAI SINGH SISODIA: It is not possible, you see.

SHRI DINESH GOSWAMI: Not possible? All right.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Gopalsamy. Please put your questions only because the time is short.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Sir, however hard the enforcement machinery may work, it is impossible to eradicate smuggling unless some constructive steps are taken to make smuggling less attractive and also less profitable.

Sir, as far as old is concerned, the Minister made a statement. The prices have been falling in the other countries and the price of gold is higher here and that is why gold is smuggled into our country. So, some steps should be taken to stop smuggling. Also, Sir, silver is going out. Will it be possible to make any equilibrium in the prices so that the smuggling activities in respect of silver could be curtailed? Also, Sir, there is a craze for imported goods, there is a mania for imported goods, like cassette taperecorders, colour TVs and electronics items. It is because prices are higher. Particularly we have imposed heavy duty and heavy taxation and penalty up to 300 per cent we have imposed. So, if the duty is reduced to a certain extent, then, definitely smuggling of these articles will become less attractive and also less profitable. I think, some time back there was a news-item in the Press that the Government was thinking of reducing the taxation on this. The Minister has also stated in his statement that sophisticated speedy boats are operating on the coast-line. I would like to know how many boats are operating on this line, because the coast from Cochin to Gujarat and West Coast is very lengthy. So unless you have a very large number of boats, you cannot control them. They easily escape; they go to narrow creeks. Previously there were. Hovercrafts. With these Hovercrafts they were able to catch them easily. I do not know whether these are operating or not. I would like to know from the hon. Minister whether the strength of the boats will be increased. Also, Sir, the smuggling going on is organized smuggling, because illegal trafic of foreign exchange also from Arab countries and from other countries to India is carried on through smugglers. That is why, Sir, some high-ups have also links with smugglers. I would like to know from the hon. Minister— my questions are...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't repeat. They have been recorded.

SHRI V. GOPALSAMY: I would like to know whether the taxation will be reduced, and also...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't repeat. I think he has noted down your points.

SHRI V. GOPALSAMY: The hon. Minister has admitted that it is very sad that Bakhia was released on bail by the Magistrate. But what happened? The authorities did not prepare themselves. They did not take any precautionary measures to launch prosecution. That also has been...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That's all right.

SHRI V. GOPALSAMY: This has been admitted by the Ministry. The Ministry did not...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This has been done already. Yes, the hon. Minister.

SHRI SAWAISINGH SISODIA: Two pertinent questions have been raised by the hon. Member. One, he says that smuggling can be controlled by reducing the tax on the various articles. Sir, this cannot be any answer to the question of smuggling or anti-smuggling action by the Government. Sir, as far as the question of smuggling is concerned, we cannot look at this act of smuggling as an isolated thing. It reflects the society as such and, therefore, unless and until there is cooperation from the whole society to the Government machinery, it is difficult to succeed in the plan or programme chalked out by the Government

Sir, as far as the anti-smuggling equipment is concerned, the distribution—In a nutshell I will put it before the House—the distribution of sophisticated Customs patrol craft and other Customs auxiliary craft among the Collectorates along the West Coast has been done according to their need. The Customs patrol craft are of Norwegian and South Korean origin. The Customs auxiliary craft comprises confiscated Arab dhows appropriated for Departmental use. Apart from the above the Customs formations are also equipped with vehicles, metal detectors, night sights, walkie talkie sets, arms and ammunitions, etc. The entire West Coast is also covered by the Customs telecommunication network for speedy and secret transmission of information relating to smuggling.

So, every possible action is being taken which is under the authority of the Government.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : माननीय मंत्री जी ने यह बयान वेस्ट कोस्ट के बारे में ही महदूद रखा है, लेकिन उस के बाद सारे देश का पिक्चर दी और जितने लोग गिरफतार हुए हैं उन की स्टेटवाइज भी तालिका रख दी। मेरा पहला सवाल भारत-नेपाल बार्डर पर स्मगलिंग के बारे में है कि पिछले तीन-चार साल के क्या आकड़े हैं आप के पास? 79 से वेस्ट-कोस्ट के बारे में आप ने बताया है। 79 से भारत-नेपाल बार्डर पर कौन-कौन सी चीजें स्मगल की जाती है, कितने एमाउन्ट की पिछली तीन-चार साल में की गयी यह हम को बतावें। दूसरे भारत-नेपाल बार्डर पर स्मगलिंग को रोकने के लिए—बीस सूत्री कार्यक्रम का लेखा-जोखा आप ने दिया कि हम यह कर रहे हैं—क्या मशीनरी आप ने बनायी है? नयी मशीनरी का आप ने जिक्र किया, मेटल डिटेक्टर वगैरह का। तो इंडो-नेपाल बार्डर पर स्मगलिंग को रोकने के लिए आप ने क्या किया? तीसरा, गिरफतार लोगों का जो ब्यौरा दिया क्या उस सबंध में यह सही नहीं है कि कुछ डिप्लोमेटस भी उसमें हैं। दो-तीन दिन पहले खबर

आयी थी अखबार में कि टूरिज्म और सिविल एविएशन का एक आफीसर कस्टम वालों ने पकड़ा। जो गिरफ्तार किये गये है उन में डिप्लोमेटस और हायर रैंक के सरकारी अफसर कितने हैं? चौथा और आखिरी सवाल यह बात ठीक उठायी गयी कि बाहर से सामान अन्दर आने को ही स्मगलिंग नहीं कहते, बल्कि अन्दर के सामान के बाहर जाने को भी कहते हैं। आप ने एक तरफ ध्यान दिया और इस ओर ध्यान नहीं दिया। सामान जाने की ही स्मगलिंग नहीं है, करेंसी की स्मगलिंग भी है। यहां से भारत के करोड़ों के नोट लेकर हवाई जहाज से काठमांडू के बैंक में जमा करने के लिए बिहार के मुख्य मंत्री ले जा रहे थे। यह बात आप को पता है या नहीं? सी० बी० आई से सीक्रेट इनफरमेशन मिली, तब रोका गया। 7 करोड़, 10 करोड़ पता नहीं कितनी करेंसी यहा से काठमांडू के बैंक में जमा करने ले जा रहे थे। इसके मुताल्लिक आप की क्या जानकारी है?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया: प्रश्न वेस्ट-कोस्ट के बारे में था। लेकिन माननीय सदस्य ने नेपाल-भारत सीमा पर स्मगलिंग के संबंध में जानकारी चाही है। वह मेरे पास उपलब्ध है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि इंडो-नेपाल बार्डर खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में 1568 किलोमीटर लम्बा है।

The administrative control along the Indo-Nepal border is exercised by our Collectors at Allahabad. Patna and West Bengal. The main items sensitive to being smuggled to India from Nepal are: synthetic fabrics, electronic goods, wrist watches and watch movements; cosmetics, sewing machine needles, etc.

The number of cases and the value of seizures since 1979 are as under. In 1979, the number of cases is 9492; in 1980, 7853; in 1981, 7294; and in 1982, 3232. The value of seizures is 135 lakhs in 1979, 161 lakhs in 1980, 207 lakhs in 1981 and 117 lakhs up to May, 1982.

Smuggling takes place both ways for imports and exports. Intelligence reports indicate that Varanasi and Patna airports continued to be used for smuggling third country goods into India from Singapore *via* Kathmandu. Recent intelligence reports also indicate that considerable quantities of third country goods are being smuggled into Nepal through post parcels and mis-declaration for ultimate deflection to India. Some of the important anti-smuggling measures adopted along the Indo-Nepal border over the recent past are to provide higher level of supervision over the preventive units and an Additional Collector of Customs has been provided at Muzaffarpur in Bihar. A separate Custom Division has been created at Naxalbari under direct supervision of an Assistant Collector. Officers of the State Police manning 10 border checkposts in far flung areas of Uttar Pradesh have been set up and they have been vested with the powers of search, seizure and arrest under the Customs Act. In view of the recent trends of smuggling of goods into India from across the border with the aid of armed escort, meetings have been held between the various officers. Some such other measures have been taken.

श्री शिव चन्द्र झा: जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं उन में कोई अफसर रैंक का भी है?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : इस की कोई जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री शिव चन्द्र झा : चीफ मिनिस्टर के बारे में भी क्या कोई जानकारी नहीं है कि जो वह एमाउन्ट ले जा रहा थे ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Kulkarni.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI (Maharashtra): Sir, in the first instance, I would request you to please give me uninterrupted time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can speak for five minutes.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: That is not enough.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is left out now. If you do not repeat, five minutes are enough.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Sir, I do not want to give the background. I will straightway come to the questions. Before going into the other items, Mr. Minister, about the Galladharis, would you like to rectify your statement because in the statement which the customs or Bombay court, it has been straightaway stated 'for political reasons'. Then, Mr. Minister, for your information, you will be protected by saying that you do not know. In the Foreign Affairs Committee. .

SHRI DINESH GOSWAMI: Which Committee?

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: In the Foreign Affairs Consultative Committee it has been stated that on this Galladhari affair the Government has to take the decision for political purposes. Only for his rectification I am suggesting this. Then, Sir, I directly come to the questions. But this thing you should rectify yourself. You are my good friend, that is what I am saying. May I know from the hon. Minister whether he has received the copy of a letter addressed to the Prime Minister, No. 305 from Bombay General Post Office, a copy of which has been handed over to my good friend, Mr. Sisodia, by Dr. Mahipat Mehta from Gujarat? Have you received that copy? And whether in that copy it has been straightway stated that the Gujarat or Kachhi or whatever his name is, Kachhi Mastan from Gujarat... (*Interruptions*). What do you want Mr. Bhandari? It has been stated in that letter that Kachhi Mastan from Gujarat is involved. They all are of different quality and character. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him put the questions.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Mastans are of a different quality and character from the Kachhi Mastan from Gujarat seven thousand tolas of gold etc. were collected. There, Sir, in that same letter it is mentioned that the Customs Collector, we are talking of political influence, the Customs Collector, Mr. Kumar, who conducted the Ahmedabad raid is now under orders of transfer. Is it due to political patronage of your friends or is it due to some other reason?

Then, Sir, I want to tell him that Dr. Mehta contacted Mr. Fotedar Mr. Bajpai, must be the General Secretary of your party, and Mr. Sisodia. Naturally you are the only Sisodia. Last February the two kingpins arrested in these raids. It is now, Sir, reliably the raids were Mastan and Bhatti and those names are mentioned in understood that this Mastan and Bhatti are going to be released by the Government because of influential political connection of the Deputy Minister of Gujarat. His name I do not know. I cannot easily find it out. I want to know whether it is a fact? If not, you should see that if you want to tighten these customs and excise organisations, the political pressures should not be brought. I only want to quote these three instances. For your information, the syndicates named in the letter are: Sumar Bottle

Haji Mastan and Zikkar Brothers; Abdulla Yakoob Bhatti; Sukar Bhakia—whom we are talking about; then Taher Mohiyuddin; Khan Brothers; Haji Noori Brothers and Wahab Galladhari. These are the seven names only that are mentioned. What action have you taken? Then about the consignments, it has been also mentioned: Silver importer at Dubai: No. Top—Abdulla Yakoob Bhatti, and Second is Sukar Bakhia. Then for Wrist Watch Exporter from Dubai, the name at the Top: Wahab Galladhari and Second: Sumar Bottle Haji Mastan. For Wahab Galladhari, it is said he has political connection. What is that political connection, I do not know. Sumar Bottle Haji Mastan receives the consignment here. Then Gold exporters from Dubai: Top: Wahab Galladhari and Second: Sumar Bottle Haji Mastan. I have mentioned this point exclusively to know from him because this letter is a registered letter and to my friend Mr. Sisodia, it was handed over by Dr. Mehta himself who is the President now of the Gujarat Pradesh Congress Committee where all these facts are mentioned. What action are you going to take?

Because yesterday the Deputy Chairman was not happy that I should be allowed to make a special mention, perhaps for the reason that this Calling Attention is coming today, I would also like to say that in Bombay—and I would like the Minister to say whether it is a fact—there is a news item dated July 20 by S. Balakrishnan, who is the reporter, and it is said that fortunately the new Chief Minister had brought one I.G. who is above board. I do not want to say anything about the last Chief Minister but this new Chief Minister at least has taken courage...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: These comments take a lot of time.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: It also takes a long time to replace the people back.

SHRI V. GOPALSAMY: Giving comments is his great asset.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: So, this Mr. Robero is a man of chaste qualities and above board. Now, the Chief Minister is under pressure to transfer this man, and pressure from whom? Pressure is from smugglers.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जिस पुलिस अफसर के बारे में आप कह रहे हैं उसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर के पास चिट्ठी आई है। उसके खिलाफ रेप केस है।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : अभी आपको मैंने नहीं कहा, मैं यह पढ़ूं तो आपको भी तकलीफ हो जाएगी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं —

In this letter of Dr. Mehta it is also mentioned here that the money has been paid to the Jana Sangh M.P. and an M.L.A. (*Interruptions*) He invited it; I did not want to read that. So, Mr. Robero has been under pressure of transfer by political personalities like Karim Lala Dongri. What Mr. Mathur is mentioning of is Dongri. Dongri is the area where all the smuggling etc. goes on; goods are loaded, unloaded paid for, brought in and even the home delivery. If you want home delivery from Dongri.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, I don't want.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: If you want a video at home, you ask this Karim Lala.

SHRI V. GOPALSAMY: At what price?

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: That I don't know. I am not a rich person. So, what I say is that you have to protect people like Kumar, like Robero and see that your political influence does not come

[Shri Arvind Ganesh Kulkarni]

in your way and these political considerations are not there to let off people like Galladharis and Bakhias etc. I do not want to say much on Bakhia because the entire episode is just like the birth of Lord Krishna. When Lord Krishna's birth takes place, the doors open and when you go away, the doors close. Similarly, Bakhia is out, then he is in and then there is the court order and everything is OK, because, money was paid right from the Lt Governor up to the chaprasi of the Goa Jail, the Aguada Jail. In the end, Sir, I would like to know what he has to say specifically on these matters which I had mentioned.

SHRI SAWAISINGH SISODIA: Sir, my respected friend, Mr. Kulkarni, has taken half of his time in mentioning Galadhari's name. He has started mentioning Galadhari and he has also mentioned the name of Galadhari when ending his speech. I am very much surprised, why he is so fond of his name, raising his name every time, even during the regime of the other party...

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: I have mentioned this during the period of the Janata rule also.

SHRI SAWAISINGH SISODIA: From 1977 to 1980. He has always been mentioning his name.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: At that time, I joined you in attacking the Janata Party for Galadhari. Kalp Nath Rai knows that he will bear me out. *(Interruptions)*

SHRI SAWAISINGH SISODIA: As far as Galadhari is concerned, I have said earlier that this case is pending before the Supreme Court. Hence, I would not like to go into the details. But I can say that our Government has no connection whatsoever with the Galadhari brothers. Whatever decision was taken, was taken on merits. This decision has also been challenged and the case is pending before the Supreme Court. I would not, therefore, go into the details. I am sure, my friend would not also like that I should go into the details. I would not like to go into the details because it is a *sub judice* matter.

As far as Dr. Mehta's letter is concerned, he has read all the contents and he has repeated it many times I have received Dr. Mehta's letter. But this is under investigation. I will not be able to say anything on this, as long as I do not receive the report of the investigation, whether there is any truth in whatever Dr Mehta has written in his letter, whether whatever he has said is based on any ground. Therefore, before the investigation is complete and the report is received, I do not want to go into the details, I would not like to say anything on the merits of the letter. This letter has been received and this is under investigation. After investigation, if there is any truth and if any action is warranted, certainly, action will be taken by the Government.

In regard to Mr. Kumar, the Collector of Customs, Ahmedabad, Mr. Kulkarni says that he is under orders of transfer. No. This is not a fact. No orders of transfer have been passed as far as Mr. Kumar, the Collector of Customs, Ahmedabad, is concerned. Hence, there is no question of any political pressure whatsoever.

In regard to the Chief Minister of Maharashtra and another officer of the Maharashtra Government, whether he is being transferred under any influence or without any influence or on any administrative grounds, I do not know. I have got no information.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: You can convey it.

SHRI SAWAISINGH SISODIA: In regard to the officer of the Maharashtra Government, I am not aware. Therefore, I am sorry, I will not be

able to say anything in regard to this. I have already replied in regard to the other matters. I would like to assure my friend, Mr. Kulkarni, that no political influence will debar or deter the Government from taking strict action against the smugglers or any other person who is found guilty.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Satyameva Jayate.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, much has been said about this smuggling on the West Coast which continues to be the main place for smuggling. This House is also conscious of the fact that this Government is taking vigorous steps, more vigorous than any other Government in the matter of checking smuggling. It is in the context of this that I rise to speak on this Calling Attention.

There are some points where the Government can be more vigilant. The hon. Minister has rightly referred to the stay orders and I can give the instance of Bakhia. He got a stay, absolutely unjustifiable, according to me, patently illegal, from the Calcutta High Court in November, 1980 and this stay continued till March, 1982. Now, of course, the High Court stay is wrong. But I would like to know from the hon. Minister, what steps were taken by the Government to get this stay vacated. Because, very often, even if the stay is erroneously given, we find that the Government does not take immediate steps for the vacation of the stay. This is the first part. The second part is about the detention of Bakhia. There is one Collectorate and the Collector of Customs, Gujarat. He operates also on the territory of Daman and Diu though Daman and Diu comes under the Union Territory of Goa. He had passed two orders of detention, one as the Collector of Gujarat and the other as the Collector of Daman and Diu, the first being prior in time. I am given to understand that after the vacation of the stay, Bakhia was arrested under the second detention order. This has the effect of rendering, possibly in law, the first order state.

Coming to the detention itself, I find that there were several irregularities. You are aware that the law of preventive detention is very technical. If the procedural safeguards are not observed, the detenu gets the benefit despite the fact that there is overwhelming material and evidence in support of detention. There are a large number of irregularities which were left. Witnesses were not produced for four and a half days in breach of the provisions of the Criminal Procedure Code. Their statements were recorded in a manner of not instilling any confidence. But what is surprising is that as many as 60 papers which were served on Bakhia were found to be blank and the Supreme Court has held that any one of these things is by itself bad enough and the detention should be set aside for not observing the procedural safeguards. This is something which the Government can avoid, ought to avoid. I would like the hon. Finance Minister to tell us whether this was a case of negligence or a case of deliberate design on the part of those officers to see that when the case went to the Advisory Board or to the High Court, Bhakia was automatically released for breach of these procedural safeguards.

There is one more aspect I want to deal with. Sir, there is a big apprehension that Sukur Narain Bakhia was never in the jail. After being lodged there, probably he was sent out. Even between 1975 and 1977, when he was under detention he managed to get the certificate of some of the topmost doctors in Bombay and remained during that period as a heart patient in St. Georges hospital. The general permission is that even in Goa jail the person who was really lodged was a double of Sukur Narain Bakhia and one of the reasons why Bakhia escaped was because the jail authorities were not anticipating

[Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare]

that on his release the Customs authorities would be ready for re-arresting him, they were not in a position to produce the real Bakhia. Therefore, they managed the escape of the second or the pseudo or the double Bakhia. So, these are the matters. Unless you have an effective machinery of punishing the kings in smuggling, nothing would be achieved. I would like you to set up a cell which would yet the detention papers before they are served, the detention orders before they are issued. You may get them approved even by the Advocate General of the State and even by the law department of the State to see that this is done effectively, and no loophole is left behind.

These are the two or three questions which I would like to ask.

SHRI SAWAISINGH SISODIA: I have already stated that Bakhia was detained under the COFEPOSA Act in 1975, after the emergency, and he was released in 1977.

SHRI V. GOPALSAMY: He was never inside the jail.

SHRI SAWAISINGH SISODIA: He was in the jail. After that, under the COFEPOSA Act on the proposal of the Government of Gujarat in the year 1980 this warrant of detention was issued. The detention order was issued on 3-4-1980 against Bakhia with a view to preventing him from smuggling goods. After that he went to the Calcutta High Court. The department got this information that the detention order had been passed but the detention order could not be executed as Bakhia went underground and obtained an order of injunction from Calcutta High Court restraining the authorities from executing that order on the plea that he was a peace-loving man, residing in Calcutta city and he had nothing to do with the alleged smuggling activities in Gujarat coast. This injunction order was, however, got vacated in March 1982. After the Department got the information of this stay order, all steps were taken. Affidavit was filed and application was submitted. The interim order was opposed by the Department and it got it vacated in March, 1982. After this, the Customs Department had kept a close watch and in pursuance of this the Goa Administration issued a detention order on 13th March, 1982, against Bakhia and his associates. This matter was placed before the Advisory Board and the Advisory Board recommended their release on technical lapses.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Not on substantial grounds.

SHRI SAWAISINGH SISODIA: This order of the Advisory Board is being examined by the Department and if anybody is found at fault, action will be taken against him.

As far as this other arrest and surrender and arrest by the Customs Department however is concerned, in this case also the petition was filed in the court of the Judicial Commissioner Goa on behalf of Bakhia by his wife challenging the legality of the detention order passed against him by the Gujarat Government. While granting an injunction restraining the authorities from executing this order pending hearing of the petition, the magistrate directed that Bakhia may be produced in court on 31-7-1982. However Bakhia surrendered on 19th July at Daman where the Customs Officers, after interrogating him, effected his arrest under the Customs Act, 1962 on the 20th July, 1982. Thereafter he was produced before the First Class Judicial Magistrate, Daman, who released him on conditional bail of Rs. 10,000 and cash security with personal bond of Rs. 10,000. This matter is also pending before the court.

Regarding Bakhia escaping from jail and other things, this is not directly under the Department of

Customs. He was in the jail of Goa, Daman and Diu Government and they are investigating it.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): Sir, the Calling Attention Notice merely draws attention to the spurt in smuggling activities. We are far from expecting that smuggling can be significantly curtailed. That is not the case partly because smuggling is an essential component of the decadent capitalism system, whether it is on the Western Coast of this country or in any part of the world. It is our unfortunate lot that we have to fight against/ decadent capitalism instead of a vigorous one.

Now through this Motion, we are trying to draw the attention of the Minister only because decadence has reached a new low. May I draw his attention to a splendid fact which has not been mentioned by any one upto now—that in our newspapers there are open advertisements for some types of watches which I suppose, are not legally imported within the country? You see periodically advertisements for several types of watches, emphasising their properties and other things. They are trying to have a good market for them. Our newspapers do carry such advertisements. I want to know from the Minister whether his attention has been drawn to that and if so, what he proposes to do about it.

The goods that are being smuggled in may conveniently be divided into two types. One type of goods are cheaper than those available in the country that is manufactured within the country. Usually these are available on the pavements of various metropolitan cities. There are all non-covert activities. These are overt activities and to plead innocence or inability to handle these only indicates the involvement of the ruling powers in the whole business. But there is another part which is associated with the conspicuous consumption of a decadent capitalist society. These are meant not only for sale within the country, even when they are brought in through the Western coastline, some times they are used to purchase also say when goods move upwards upto Haryana.

Now my question is very simple. To the extent you call it conspicuous consumption, I entirely agree with the reply that the hon. Minister gave. It is certainly related to the system, the social conditions, the approach which is generated by the socio-economic structure, and the Government, as the representatives and the reinforcing factor of that socio-economic structure is unable to curtail that. Perhaps, to curtail that one requires a change in the socio-economic structure and its leadership as represented in the Government. But my question is this: If it can be established that most of the smuggled goods are used for conspicuous consumption, is there any thinking in the mind of the Ministry to curb such conspicuous consumption? So long as they cannot do it, they cannot stop this kind of smuggling activity.

My experience of the West Coast is too little, but I know places even associated with religious names also. I know of a spot in West Bengal at the northern tip bordering Nepal which is called Pashupatinath, near a new centre opened by the West Bengal Government for purposes of tourism. Any day one visits that place, one sees large numbers of very posh imported cars waiting there to receive smuggled goods. Now, any vigorous Government representing even vigorous capitalism would have stopped that. Now, why are not such things being stopped?

The reply that measures are being taken in relation to bail orders by the courts is also entirely unsatisfactory. We all know that courts pass orders even with the egging on by the prosecution. The prosecution behaves in a manner that it becomes not only permissible but imperative for the

courts to issue the orders. Then they say that the court has acted in this manner, what can we do? My question is, what punitive steps have been taken against the prosecution side when all those issues were raised before the court and which led the court to pass such a judgement? I want an answer to this.

SHRI SAWAI SINGH SISODIA: Sir, there are two points raised by the hon. Member. First of all, he has pointed out some defects in the prosecution and the follow-up process. Sir, the department is quite vigilant and we do try to find out if there are some defects or loopholes in the procedure which is being followed by the department and, so, care is being taken. Regarding spurious goods being sold in the market, certainly this is very unfortunate that things which are manufactured in our country are marked as manufactured in foreign countries and they are being sold in the country. It is because of the attraction people have towards foreign goods, smuggled goods. But whenever such instances are brought to our notice or are seen by the department, appropriate action is taken. Moreover, this is an individual thing. After all, the Government cannot go and force and teach every individual that they must not have any attraction for foreign goods. It is the thinking and will of individuals which goes on in the society. We see in many cases that the spurious goods seized by the department, after investigation, are all made in our country and they are marked as made in foreign countries. So, whenever such people are caught, action is taken. And really it is a matter of great concern to us that on the Indo-Nepal border there are many incidents of smuggling. About the action taken, I have given the details in reply to Mr. Jha's queries. Various actions have been taken by the Department to curb the smuggling activities on the Indo-Nepal border.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Special mentions will be taken up at 5 P.M. Messages from the Lok Sabha Secretariat.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

(I) The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1982.

(II) The Chaparmukh-Silghat Railway line and the Katakhal-Lalabazar Railway Line (Nationalisation) Bill, 1982.

(III) The Metro Railways (Construction of Works) Amendment Bill, 1982.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:-

(I)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1982, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 21st July, 1982."

(II)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Chamarmukh-Silghat Railway Line and the Katakhal-Lalabazar Railway Line (Nationalisation) Bill, 1982, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 21st July, 1982."

(III)

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to